<u>उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल</u>

<u>रिट याचिका (एस/एस) संख्या 1451 वर्ष 2020</u>

दिनेश तिवारी ..... याचिकाकर्ता

बनाम

जिला न्यायाधीश हरिद्वार और अन्य .....प्रतिउत्तरदाता

श्री आलोक महरा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से ।
श्री शोभित सहारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से ।

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार शर्मा, (मौखिक)</u>

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, जो जिला एवं सत्र न्यायालय, हरिद्वार, जिला हरिद्वार में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत था, ने प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2020 को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए यह रिट याचिका दायर की थी, जिसके तहत, उपयुक्तता परीक्षा आयोजित करने के लिए 22.11.2020 को तय की गई थी, और आगे उत्तरदाताओं को जिला न्यायालय , हरिद्वार, में लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्तता परीक्षा आयोजित करने का आदेश देने के लिए परमादेश रिट के माध्यम से प्रार्थना की गई है, "2011 के सेवा नियमों में लिपिकवर्गीय संवर्ग के पद की पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि का निर्धारण" के अनुसार और स्टाफिंग पैटर्न भी उसी तरह से किया जाना है, जैसा कि उत्तराखंड के अन्य जिला न्यायालय में किया गया है।

2. याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापना सेवा नियम 2007 के अनुसार, नियम 20 में वह प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो जिला न्यायाधीश द्वारा पदों पर चयन के प्रयोजनों के लिए अपनाई जानी है, जिन्हें पदोन्नति के माध्यम से; वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर भरना आवश्यक है।

3. याचिकाकर्ता का तर्क है कि परंतुक के अंतर्गत नियम, जिन्हें 01.06.2011 पर अधिसूचित किया गया था, वास्तव में, वर्ष 2011 में लागू किए गए नियम, प्रचलित नियमों के लिए अपर्याप्त थे स्टाफिंग पैटर्न के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए या लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता पर विचार करने के उद्देश्यों के लिए क्षेत्र को नियंत्रित करना। इस प्रकार लागू किए गए नियम, जिन्हें वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा लागू करने की मांग की गई है, जैसा कि वर्ष 2011 में अधिसूचित किया गया था, बाद में एक संशोधन के माध्यम से एक संशोधन भी किया गया था, जिसे दिनांक 09.04.2015 की अधिसूचना द्वारा किया गया था, जिसमें लिपिकवर्गीय न्यायालय कर्मचारी संवर्ग की परिभाषा का दायरा बढ़ाते हुए नियम 3 (डी) में संशोधन किया गया था, और तदनुसार लिपिकवर्गीय संवर्ग के कर्मचारियों की परिभाषा के विस्तार के साथ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद को 2011 के नियमों के से परिभाषित लिपिकवर्गीय संवर्ग के कर्मचारियों की परिभाषा में शामिल किया गया था।

4. 2011 के नियमों को दी गई उक्त व्याख्या के आधार पर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यदि नियमों के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, और जैसा कि वर्ष 2011 में अधिसूचित किया गया था, तो याचिकाकर्ता के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने के दावे को उक्त नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए, और इसलिए कार्यालय ज्ञापन, जिसे 06.10.2015 पर जारी किया गया था, जैसा कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.07.2016 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें कर्मचारी विन्यास में संशोधन किया गया था, अब तक यह मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद से संबंधित था, यह आरोप लगाते हुए कि इसे 2% से 6% तक बढ़ाकर, प्रशासनिक अधिकारियों के पोषण संवर्ग के पद से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना आवश्यक था, और पदोन्नति संवर्ग में यह कमी मनमाना थी।

5. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत सेवाओं में लिपिकवर्गीय संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति के उद्देश्यों पर विचार करते हुए, पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता का निर्धारण प्रतिवादी/राज्य द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, जो उत्तराखंड राज्य के अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों और परिवार न्यायालयों के कर्मचारियों के स्टाफिंग पैटर्न को भी विनियमित करेगा।

6. उपरोक्त दलीलों के आधार पर, याचिकाकर्ता तर्क दिया कि उत्तराखंड राज्य के से लिपिक संवर्ग संरचना, अब तक यह उत्तराखंड राज्य के अधीनस्थ और पारिवारिक न्यायालयों से संबंधित है, क्योंकि इसे दिनांक 1 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पुनर्गठित किया गया था, तदनुसार हरिद्वार के जिला न्यायाधीश में लिपिक संवर्ग की स्वीकृत संख्या का आकलन 185 के रूप में किया गया था, जो आशुलिपिक को छोड़कर होगा, और इसलिए याचिकाकर्ता का तर्क है कि 2011 के नियमों के अनुसरण में स्टाफिंग पैटर्न को अपनाने के परिणामस्वरूप, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1 के आधार पर पुनर्गठित स्टाफिंग पैटर्न, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद, जिसे प्रशासनिक अधिकारी के पोषण संवर्ग से भरा जाना आवश्यक था, 15 पद हैं। उनका तर्क है कि उत्तराखंड राज्य में अधीनस्थ, सिविल और परिवार न्यायालयों में स्टाफिंग पैटर्न के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, दो बार पदोन्नति अभ्यास, जो 2011 के नियमों के से आयोजित किया गया था, कथित तौर पर पदोन्नति अभ्यास 17.08.2017 और 17.01.2018 पर आयोजित किया गया था, और याचिकाकर्ता का तर्क है कि चूंकि वह पात्र था, और वह प्रतिलिपिकार के पद पर काम कर रहा था, इसलिए उसे प्रशासनिक अधिकारी के पद पर माना गया और पदोन्नत किया गया, जिसे बाद में नए अपनाए गए स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार फिर से नामित किया गया।

7. याचिकाकर्ता का तर्क है कि इसके परिणामस्वरूप 2011 के नियमों के निहितार्थ, प्रतिवादी द्वारा लिया गया निर्णय, जो वर्तमान रिट याचिका में विवादित है, वह

विभागीय पदोन्नति समिति का निर्णय है, जैसा कि 02.08.2020 पर जारी किया गया था, अपनी बैठक में जो 10.07.2020 पर आयोजित की गई थी, जिसके तहत योग्य उम्मीदवारों की उपयुक्तता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसने वास्तव में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था। जिससे क्षुब्ध होकर प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता सहित अन्य लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति पद हेतु उपयुक्तता परीक्षा आयोजित करने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उठाये गये कदम, 2011 के नियम, के विपरीत हैं और विशेष रूप से, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तर्क के आधार पर कहना है कि 2011 के नियम उनके कैडर के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, हालांकि यह उत्तराखंड राज्य के कार्मिक विभाग द्वारा 01.06.2011 को अधिसूचित राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में है। यही अधीनस्थ लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की सेवाओं और सेवा शर्तों को भी नियंत्रित करेगा, और 2011 के नियमों के नियम 3 और 2011 के नियमों के नियम 4 में दी गई परिभाषा से वह जो निहितार्थ प्राप्त कर रहा है, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को परिभाषित किया गया है, जहां पोषण संवर्ग प्रदान किया गया है, उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जिसने न्यूनतम 2 साल की सेवा पूरी कर ली है।

8. याचिकाकर्ता का तर्क है कि उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने से इनकार किया गया; पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए, और उसे पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए अयोग्य ठहराना 2011 के नियमों के निहितार्थों के विपरीत है, और इसलिए उसने मांग की है कि 22.10.2020 को लिया गया निर्णय, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित किया गया था, उपयुक्तता परीक्षण आयोजित करने की तिथि तय करना, और पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि के निर्धारण के लिए परिणामी पदोन्नति अभ्यास, यह 2011 के नियमों के अनुसार होना चाहिए।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाबी शपथ पत्र दायर किया था और जवाबी शपथ पत्र में उन्होंने एक विशिष्ट रुख अपनाया है कि वर्ष 2011 में घोषित नियम, जो कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत सेवाओं में लिपिक संवर्ग के पद से पदोन्नति की पात्रता अवधि का निर्धारण है, जैसा कि 01.06.2011 पर अधिसूचित किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय के लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू किए गए विशेष नियमों पर हावी नहीं होंगे, जिसे उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापना नियम, 2007 के रूप में नामित किया गया है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 2011 के अधिनियम की धारा 2 और 2007 में बनाए गए नियमों के अनुसार, पदोन्नति अभ्यास सहित सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सामान्य प्रावधानों पर एक अधिभावी प्रभाव दिया गया है। राज्य सरकार के विभागों में किया जाना है, क्योंकि वे राज्य विभाग अधीनस्थ न्यायालय में प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सेवा शर्तों से स्वतंत्र होते हैं, जिनकी सेवाएं उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर शासित होती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जहां उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों और उसके तहत काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर अपना सीधा नियंत्रण रखता है

11. पैराग्राफ संख्या 19 में उत्तरदाताओं ने, पैराग्राफ संख्या 12 में उठाई गई दलीलों के आलोक में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, जिसमें याचिकाकर्ता ने कुछ उदाहरण रखे थे, जहां पदोन्नति की कवायद 2011 के नियमों के तहत की जा रही थी, और इस संबंध में याचिकाकर्ता ने जिन उदाहरणों पर भरोसा किया है उनमें से एक 17.08.2017 और 17.01.2018 की पदोन्नति प्रक्रिया का है, जैसा कि संलग्नक संख्या 7 के रूप में संलग्न है, रिट याचिका, जो दोनों जिला हरिद्वार से संबंधित हैं।

12. रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 12 में उठाई गई दलीलों के जवाब में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह उत्तर दिया गया है कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 12 में संदर्भित उक्त निर्णय किसी को कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता; वर्तमान मामले में पदोन्नति देने पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि दो गलतियाँ याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसी स्थिति नहीं बनाती हैं जहाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को नकारात्मक समानता के सिद्धांतों को आकर्षित करने के लिए आकर्षित किया जा सके। , एक अधिकार जिसे कानून के तहत लागू किया जा सकता है वह हमेशा मौजूदा लागू नियमों पर आधारित होना चाहिए। वास्तव में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने जवाबी शपथ पत्र का उल्लेख किया है, जिसमें, पैराग्राफ संख्या 4 में, यह तर्क दिया गया है कि जहां तक अधीनस्थ न्यायालयों के अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंधित विनियमन का संबंध है, इसे अनिवार्य रूप से मात्र उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 235 इस प्रकार हैः-

> "235. जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें किसी राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित और जिला न्यायाधीश के पद से हीन कोई पद धारण करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति और उन्हें अनुमति प्रदान करना शामिल है, उच्च न्यायालय में निहित होगा, लेकिन इस अनुच्छेद की किसी भी बात का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से अपील करने का कोई अधिकार छीनने के रूप में नहीं लगाया जाएगा जो उसे अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाली कानून के से हो सकता है या उच्च न्यायालय को ऐसी कानून के से निर्धारित उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार अन्यथा उससे निपटने के लिए अधिकृत करता है।"

13. वास्तव में, भारत के संविधान का अनुच्छेद 235 जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के उद्देश्यों के

लिए अपने अधीनस्थ न्यायालयों की सेवा शर्तों पर उच्च न्यायालय के विशेष नियंत्रण की परिकल्पना और सुरक्षा करता है, जिसमें उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और राज्य की सेवाओं के न्यायिक संवर्ग से संबंधित व्यक्तियों को छुट्टी देना और "जिला न्यायाधीश के पद से हीन" कोई भी पद धारण करना शामिल है, कानून के अंतर्गत इसे विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत उसके अनुमोदन पर या उसके पश्चात प्रयोग करने के लिए निहित किया गया है।

14. प्रतिवादी नंबर 3 के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया था कि जहां तक याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क का संबंध है; अधीनस्थ न्यायालयों में स्टाफिंग पैटर्न को 2011 के नियमों के तहत निहित प्रावधानों को निकालकर लागू किया गया था, यह उनके आदेश पर एक गलत नाम है; इसका कारण यह है कि प्रतिवादी संख्या 3 के अनुसार, वास्तव में, यह उत्तराखंड का उच्च न्यायालय था, जिसने पहले ही एक परिपत्र संख्या 2176/यूएचसी/एडमिन बी/XVI-55 -2010, दिनांक 06.05.2016 जारी कर दिया था। जिसमें, राज्य द्वारा 06.10.2015 को जारी सरकारी आदेश/कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित मानदंडों के मद्देनजर, मंत्रालयिक संवर्ग के स्टाफिंग पैटर्न और अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों के लिपिक संवर्ग को शासित किया गया था। उत्तराखंड के. मतलब, याचिकाकर्ता के वकील का तर्क यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों का स्टाफिंग पैटर्न 2011 के नियमों पर आधारित था, जिसे उत्तराखंड उच्च के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी परिपत्र के मद्देनजर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों के लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के स्टाफिंग पैटर्न को विनियमित करता है।

15. तर्क का एक और पहलू है, जिसे प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तारित किया है, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के निहितार्थ और अधीनस्थ न्यायालयों और विशेष रूप से लिपिकवर्गीय संवर्ग पर शासन की शक्तियों

के प्रयोग के दायरे के बारे में उपरोक्त सिद्धांत, जिसके साथ हम तत्काल मामले में अधिक चिंतित हैं, वास्तव में, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा एक रिट याचिका डब्ल्यूपीएसबी नंबर 467 वर्ष 2019 "प्रकाश चंद्र बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य" में दिए गए फैसले के पैराग्राफ नंबर 6 के मद्देनजर, जो यहां नीचे निकाला गया है: -

> "6. उत्तराखंड सेवा में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली में 2014 का संशोधन, जिसके से ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 42 वर्ष कर दिया गया था, सरकार के अंतर्गत सेवाओं में नियुक्ति के मामले में लागू होता है। चूंकि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ उत्तराखंड राज्य में सिविल न्यायालयों और परिवार न्यायालयों के लिपिकवर्गीय संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं, इसलिए सामान्य नियमों में किए गए 2014 के संशोधन के परिणामस्वरूप 2007 के नियमों के नियम 7 का अतिक्रमण नहीं होगा। यह मात्र तभी है जब 2007 के नियमों को 2014 के नियमों के अनुरूप लाने के लिए संशोधित किया जाता है, तो ऐसे किसी भी संशोधन द्वारा निर्धारित ऊपरी आयु सीमा को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ उत्तराखंड राज्य में सिविल न्यायालयों और परिवार न्यायालयों के लिपिकवर्गीय संवर्ग में समूह सी पदों पर नियुक्ति के लिए की गई भर्ती प्रक्रिया पर लागू किया जा सकता है। चूंकि 2007 के नियम, जिनमें संशोधन नहीं किया गया है, सिविल न्यायालयों और परिवार न्यायालयों के लिपिकवर्गीय संवर्ग में समूह सी पदों पर लागू होने वाले विशेष नियम हैं, सामान्य नियमों में 2014 के बाद के संशोधन के बावजूद इसका नियम 7 प्रबल होगा।"

16. इसमें प्रावधान किया गया है कि चूंकि विधानमंडल ने उत्तराखंड राज्य में सिविल अधीनस्थ न्यायालयों और पारिवारिक न्यायालयों के लिपिकवर्गीय संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्टाफिंग पैटर्न सहित सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के

लिए जानबूझकर अलग-अलग नियम बनाए हैं, इसलिए सामान्य नियम लागू होते हैं। सरकारी सेवकों पर यह लागू नहीं होगा, यहां तक कि वर्ष 2014 में संशोधित भी। वास्तव में बनाए गए नियमों को विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू करने के लिए उन्हें सामान्य नियमों पर अधिभावी प्रभाव दिया गया है, जिन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू किया जा रहा है, जैसा कि 2011 के नियमों को लागू करने से तत्काल मामले में होता है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल मामले में भी लागू करने की मांग की जा रही है ताकि उसे एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने की प्रकृति में राहत मिल सके।

17. विशिष्ट शासी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जिनके पास खण्ड पीठ द्वारा उसमें निर्धारित किए गए और सचिव द्वारा उत्तराखंड सरकार को जारी किए गए परिपत्र के आलोक में, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुरूप चलता है, ऊपर दिए गए कारणों से, सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर लागू होने वाले उक्त अलग नियमों को एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के याचिकाकर्ता के अधिकार को बनाए रखने के लिए लागू करने के लिए उधार नहीं लिया जा सकता है, स्टाफिंग पैटर्न को आकर्षित करके, जिसकी परिकल्पना 2011 के नियमों में की गई थी, क्योंकि अधीनस्थ अदालतों का स्टाफिंग पैटर्न विशेष रूप से कार्यकारी निर्देश द्वारा नियंत्रित होता है, जो उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसरण में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। इसलिए 2011 के नियमों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक विरुद्ध एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप विरुद्ध पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार परमादेश के लिए अनिवार्य रिट जारी परमादेश के लिए याचिकाकर्ता का दावा स्थायी नहीं है, विशेष रूप से जब 2011 के नियम, स्वयं अधीनस्थ अदालतों पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार, रिट याचिका में गुण-

दोष का अभाव है और वह विफल हो जाती है और तदनुसार उसे खारिज कर दिया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति)

21.12.2021

एनआर/